

ग्रामीण कृषि श्रमिकों की रोजगार संरचना" (उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के विशेष संदर्भ में)

सुभिता सिंह¹, मृदुला मिश्रा²

¹ शोध छात्रा, अर्थशास्त्र एवं ग्रामीण विकास विभाग, डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, भारत

² प्रोफेसर, अर्थशास्त्र एवं ग्रामीण विकास विभाग, डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, भारत

DOI: <https://doi.org/10.66856/ijrh.2026.8.2.8032>

सारांश

भारत की अर्थव्यवस्था का आधार ग्रामीण क्षेत्र है, जिसमें कृषि और उससे सम्बद्ध गतिविधियों की केंद्रीय भूमिका रही है। ग्रामीण कृषि श्रमिक इस व्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं, क्योंकि कृषि उत्पादन की अधिकांश प्रक्रियाएँ इन्हीं के श्रम पर निर्भर करती हैं। उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिला पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख कृषि-प्रधान जिला है, जहाँ की सामाजिक-आर्थिक संरचना में ग्रामीण कृषि श्रमिकों की संख्या सर्वाधिक है। सीमित भूमि जोत, जनसंख्या दबाव, पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ तथा औद्योगिक विकास का अभाव यहाँ की रोजगार संरचना को विशेष रूप से प्रभावित करता है।

यह शोध-पत्र जौनपुर जिले के ग्रामीण कृषि श्रमिकों की रोजगार संरचना का बहुआयामी अध्ययन प्रस्तुत करता है। अध्ययन में कृषि-आधारित रोजगार, मौसमी एवं अस्थायी रोजगार, गैर-कृषि कार्यों की ओर बढ़ती प्रवृत्ति, ग्रामीण-शहरी प्रवासन, आय स्तर तथा जीवन-यापन की दशाओं का विश्लेषण किया गया है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार कृषि कार्य की मौसमी प्रकृति ग्रामीण कृषि श्रमिकों को अर्द्ध-बेरोजगारी और आर्थिक असुरक्षा की स्थिति में धकेलती है।

शोध में यह पाया गया है कि जौनपुर जिले के अधिकांश कृषि श्रमिक निम्न मजदूरी, अनियमित रोजगार, सामाजिक सुरक्षा के अभाव तथा शिक्षा और कौशल की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य सरकारी योजनाओं ने कुछ हद तक राहत प्रदान की है, किंतु इन योजनाओं का लाभ सभी पात्र श्रमिकों तक समान रूप से नहीं पहुँच पा रहा है।

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण कृषि श्रमिकों की वर्तमान रोजगार संरचना को समझना, उनकी सामाजिक-आर्थिक समस्याओं की पहचान करना तथा क्षेत्रीय विकास के संदर्भ में व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना है। यह शोध-पत्र नीति-निर्माताओं, शोधार्थियों तथा ग्रामीण विकास से जुड़े अध्ययनकर्ताओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है तथा भविष्य में जौनपुर जैसे कृषि-प्रधान जिलों में रोजगार सृजन एवं श्रमिक कल्याण की दिशा में ठोस आधार प्रदान करता है।

मूल शब्द: ग्रामीण, कृषि श्रमिक, रोजगार, उ.प्र. जौनपुर

भारत एक कृषि-प्रधान देश है, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है और इसी के साथ ग्रामीण कृषि श्रमिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये श्रमिक न केवल फसल उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं—जैसे जुताई, बुवाई, निराई-गुड़ाई, कटाई एवं मड़ाई—में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं, बल्कि कृषि व्यवस्था को गतिशील बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके बावजूद, ग्रामीण कृषि श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर बनी हुई है।

ग्रामीण कृषि श्रमिकों की स्थिति को समझने के लिए उनकी रोजगार संरचना का अध्ययन आवश्यक है। रोजगार संरचना से आशय है—रोजगार के प्रकार, उसकी निरंतरता, मौसमी स्वरूप, मजदूरी दर, कार्य की शर्तें तथा उससे प्राप्त आय। भारत के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि रोजगार अस्थायी और मौसमी होता है, जिसके कारण श्रमिकों को वर्ष के कई महीनों तक बेरोजगारी या अर्द्ध-बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। यही स्थिति ग्रामीण गरीबी, ऋणग्रस्तता और सामाजिक असुरक्षा को जन्म देती है।

उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जहाँ कृषि श्रमिकों की संख्या भी अत्यधिक है। राज्य के पूर्वी भाग में स्थित जौनपुर जिला कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। यहाँ की उपजाऊ भूमि, अनुकूल जलवायु और पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ कृषि उत्पादन को बढ़ावा देती हैं, किंतु भूमि जोत का निरंतर विखंडन, बढ़ती जनसंख्या और सीमित औद्योगिक विकास के कारण कृषि श्रमिकों के लिए स्थायी रोजगार के अवसर सीमित हैं। परिणामस्वरूप, बड़ी संख्या में लोग कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करने को विवश हैं।

जौनपुर जिले में ग्रामीण कृषि श्रमिकों की रोजगार संरचना अनेक समस्याओं से ग्रस्त है। कम मजदूरी, कार्य की अनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, शिक्षा और कौशल विकास के सीमित अवसर तथा मौसमी बेरोजगारी यहाँ की प्रमुख विशेषताएँ हैं। कृषि कार्य के अतिरिक्त उपलब्ध वैकल्पिक रोजगार के अवसर भी सीमित हैं, जिसके कारण श्रमिकों को अस्थायी प्रवासन की ओर जाना पड़ता है। यह प्रवासन न केवल उनके पारिवारिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी नई समस्याएँ उत्पन्न करता है।

इन्हीं परिस्थितियों के प्रकाश में प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य जौनपुर जिले के ग्रामीण कृषि श्रमिकों की रोजगार संरचना का विस्तृत अध्ययन करना है। इस अध्ययन के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया है कि ग्रामीण कृषि श्रमिक किस प्रकार के रोजगार में संलग्न हैं, उनकी आय और जीवन स्तर क्या है, तथा वे किन सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। साथ ही, यह शोध ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन से संबंधित नीतियों के लिए उपयोगी सुझाव प्रस्तुत करने का भी प्रयास करता है, जिससे ग्रामीण कृषि श्रमिकों की स्थिति में सुधार संभव हो सके।

संबंधित शोध साहित्य का अध्ययन

जौनपुर जिले में ग्रामीण कृषि श्रमिकों की रोजगार संरचना अनेक समस्याओं से ग्रस्त है। जिसके विशय में विभिन्न विद्वानों ने अपने-अपने मत व्यक्त किए हैं।

Kumar et al. (2023) ने भारतीय कृषि श्रमिकों के रोजगार संरचना पर एक सांख्यिकीय विश्लेषण प्रस्तुत किया। इस

अध्ययन में पाया गया कि कृषि क्षेत्र भारत में बढ़ती ग्रामीण श्रमिक शक्ति को प्रभावी रूप से रोजगार नहीं दे पा रहा है, और कृषि श्रमिकों का निर्धनता-ग्रस्त स्वरूप तथा रोजगार अस्थिरता प्रमुख समस्याएँ बनी हुई हैं।

Sant Kumar et al. (2023) ने भारत में कृषि मजदूरी के रुझान और निर्धारकों पर शोध किया। इस अध्ययन में कृषि मजदूरों की मजदूरी को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे गैर-कृषि मजदूरी, मनरेगा, साक्षरता और सिंचाई सुविधाओं की भूमिका को रेखांकित किया गया है।

Zaki Ahmad (IERJ) का अध्ययन भारत के ग्रामीण श्रम पर व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर निर्भर रोजगार, प्रवासन तथा रोजगार अवसरों में कमी जैसी चुनौतियों पर जोर दिया गया है।

Gari (Rural Labour Patterns in Jharkhand) ने ग्रामीण झारखंड में महिलाओं की कृषि श्रम भागीदारी का वर्णनात्मक विश्लेषण किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि कृषि श्रम संरचना को प्रभावित करती है और उसे और अधिक जटिल बनाती है।

Sneha S B et al. (2024) ने कृषि मजदूरी में रुझानों और संरचनात्मक परिवर्तनों पर विश्लेषण किया। उनका अध्ययन स्पष्ट करता है कि मनरेगा जैसा रोजगार ढाँचा खेती में मजदूरी को प्रभावित करता है और समय-समय पर मजदूरी में अंतर तथा असमानता उत्पन्न करता है।

Chinnam Naidu का शोध कृषि मजदूरों के कानूनी नियमन पर केंद्रित है और दिखाता है कि मौसमी बेरोजगारी तथा कृषि श्रम की अस्थिरता आज भी भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मुख्य समस्या बनी हुई है, जिसका समाधान सरकार की योजनाओं और श्रम नियमों के सुधार से संभव है।

Patavardhan & Leelavathi (2013) ने भारतीय ग्रामीण श्रम आपूर्ति और कृषि विकास पर अध्ययन किया। उनके निष्कर्ष बताते हैं कि ग्रामीण-शहरी प्रवासन और मनरेगा जैसे सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रमों से ग्रामीण श्रम बाजार पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जिससे कृषि श्रमिकों की उपलब्धता और मजदूरी स्तर में बदलाव आया है।

Kumar et al. (2019) ने पूर्वी भारत के आदिवासी ग्रामीण इलाकों में रोजगार और आजीविका की बदलती पैटर्न व्यवस्था पर अध्ययन किया। यह शोध दिखाता है कि कृषि आधारित रोजगार के साथ-साथ गैर-कृषि आजीविका के अवसर भी ग्रामीण जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

Surender (2022) ने भारतीय कृषि श्रमिकों की समस्याओं पर एक विश्लेषण प्रस्तुत किया, जिसमें ग्रामीण श्रमिकों की कम मजदूरी, ऋणग्रस्तता, मौसमी रोजगार, आंदोलन और सामाजिक असुरक्षा जैसी प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है।

Tiwari & Prawal (2025) ने कृषि श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, मजदूरी अंतर और आजीविका में बदलते रुझानों का विश्लेषण किया है। यह शोध आधुनिक कृषि संरचना में मजदूरों के रोजगार अवसरों और उनके सामाजिक जीवन पर तकनीकी बदलावों के प्रभाव को रेखांकित करता है।

Bhattacharya et al. (2023) ने ग्रामीण भारत में वर्कफेयर रोजगार तक पहुँच और उसके नेटवर्क संबंधों पर शोध किया है। उनके विश्लेषण के अनुसार सामाजिक नेटवर्क और संबंधों का ग्रामीण रोजगार तक पहुँच पर गहरा प्रभाव होता है।

Nag (2023) ने एक शोध में देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय बिजली के उपलब्ध होने से कृषि मजदूरी पर प्रभाव पड़ता है और यह कृषि श्रमिकों के रोजगार और मजदूरी पर सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव दोनों डालता है।

डी. एन. धनागरे (1994) ने ग्रामीण भारत में वर्ग-संरचना का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट किया है कि कृषि श्रमिक सबसे

अधिक शोषित वर्ग हैं, जिनकी रोजगार संरचना अस्थायी और असुरक्षित बनी रहती है। उनके अनुसार भूमि स्वामित्व का असमान वितरण कृषि श्रमिकों की निर्धनता का प्रमुख कारण है।

बी. एच. हान्सन (2001) के अध्ययन में ग्रामीण श्रम बाजार की संरचना पर प्रकाश डाला गया है। वे बताते हैं कि कृषि रोजगार की मौसमी प्रकृति श्रमिकों को वैकल्पिक आजीविका की तलाश के लिए विवश करती है।

ताराचंद (2005) ने उत्तर भारत के कृषि श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक दशा का अध्ययन करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि न्यूनतम मजदूरी कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन न होना ग्रामीण श्रमिकों की स्थिति को और कमजोर बनाता है।

अमर्त्य सेन (2006) ने अपनी क्षमतावादी दृष्टि के माध्यम से यह प्रतिपादित किया कि केवल आय ही नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुरक्षा भी ग्रामीण श्रमिकों के विकास के लिए आवश्यक है। कृषि श्रमिक इन क्षमताओं से वंचित पाए जाते हैं।

जी.एस. भल्ला (2008) ने भारतीय कृषि में रोजगार प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हुए बताया कि कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी कृषि श्रमिकों की प्रमुख समस्या है।

एन.सी. सक्सेना (2010) के अनुसार ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ तब तक सीमित रहेगा, जब तक कृषि के बाहर स्थायी रोजगार के अवसर विकसित नहीं किए जाते। उनका अध्ययन पूर्वी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में विशेष रूप से प्रासंगिक है।

बी.एल. अग्रवाल (2011) ने ग्रामीण गरीबी और कृषि श्रमिकों की समस्याओं पर अध्ययन करते हुए यह निष्कर्ष दिया कि भूमिहीनता और ऋणग्रस्तता रोजगार अस्थिरता को और गहरा करती है।

पी.के. धर (2012) ने कृषि श्रमिकों की मजदूरी संरचना का विश्लेषण करते हुए बताया कि क्षेत्रीय असमानताएँ मजदूरी दरों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में।

अरुणा शर्मा (2014) ने ग्रामीण महिला कृषि श्रमिकों की स्थिति पर अध्ययन करते हुए यह स्पष्ट किया कि महिला श्रमिकों को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी और अधिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है।

रामकुमार एवं सिंह (2015) के अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि मनरेगा जैसी योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं, किंतु कृषि श्रमिकों की दीर्घकालिक समस्याओं का समाधान अभी अधूरा है।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व :

जौनपुर जैसे कृषि-प्रधान जिले में वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार की अधिकता तथा अन्य महीनों में तीव्र अभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। इस असंतुलित रोजगार संरचना के कारण आय-अस्थिरता, ऋणग्रस्तता, कुपोषण, शिक्षा में बाधा तथा अस्थायी प्रवास जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिला पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख कृषि-प्रधान जनपद है, जहाँ बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवार कृषि श्रम पर निर्भर हैं। इस क्षेत्र में सीमित औद्योगिक विकास, कम गैर-कृषि रोजगार अवसर तथा कृषि की मौसमी प्रकृति के कारण श्रमिकों को बेरोजगारी, अल्प-रोजगारी और प्रवासन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद जौनपुर जिले के ग्रामीण कृषि श्रमिकों की रोजगार संरचना पर केंद्रित व्यवस्थित एवं गहन अध्ययन अपेक्षाकृत कम उपलब्ध हैं। यह शोध इसी कमी को पूरा करने का प्रयास करता है।

अध्ययन की आवश्यकता इस तथ्य से भी जुड़ी हुई है कि ग्रामीण कृषि श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण गरीबी, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास से संबंधित है। यदि इस वर्ग की रोजगार संरचना सुदृढ़ नहीं होती, तो ग्रामीण

विकास की समस्त योजनाएँ सीमित प्रभाव ही छोड़ पाएँगी। अतः कृषि श्रमिकों के रोजगार स्वरूप, मजदूरी, कार्य-अवधि, मौसमी बेरोजगारी तथा वैकल्पिक आजीविका के अवसरों का विश्लेषण करना नीतिगत दृष्टि से अनिवार्य है।

अध्ययन का महत्व

यह अध्ययन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत अध्ययन का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है—

- यह अध्ययन जौनपुर जिले के ग्रामीण कृषि श्रमिकों की रोजगार संरचना को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है, जिससे उनकी वास्तविक सामाजिक-आर्थिक स्थिति को समझने में सहायता मिलती है।
- अध्ययन ग्रामीण कृषि श्रमिकों की मौसमी बेरोजगारी, अल्प-रोजगारी तथा आय की अनिश्चितता जैसी समस्याओं को रेखांकित करता है, जो ग्रामीण गरीबी के प्रमुख कारण हैं।
- यह शोध कृषि एवं गैर-कृषि रोजगार के बीच बढ़ते अंतर्संबंध को उजागर करता है तथा प्रवासन की प्रवृत्ति को समझने में सहायक है।
- अध्ययन के निष्कर्ष नीति-निर्माताओं और प्रशासकों को ग्रामीण रोजगार सृजन से संबंधित योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
- यह शोध मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं अन्य सरकारी कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आंकलन करने में सहायक सिद्ध होता है।
- अध्ययन ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास एवं वैकल्पिक आजीविका के अवसरों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- अकादमिक दृष्टि से यह शोध ग्रामीण श्रम, कृषि रोजगार संरचना एवं क्षेत्रीय विकास से संबंधित साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
- यह अध्ययन भविष्य के शोधार्थियों के लिए संदर्भ सामग्री के रूप में उपयोगी है, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं जौनपुर जिले पर केंद्रित शोध हेतु।
- सामाजिक दृष्टि से यह अध्ययन एक उपेक्षित वर्ग की समस्याओं को उजागर कर उनके समाधान की दिशा में सकारात्मक चेतना उत्पन्न करता है।
- समग्र रूप से यह शोध ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन तथा समावेशी आर्थिक विकास की दिशा में उपयोगी आधार प्रदान करता है।

अध्ययन के उद्देश्य

- प्रस्तुत शोध-अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—
- उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में ग्रामीण कृषि श्रमिकों की रोजगार संरचना का विस्तृत अध्ययन करना।
- ग्रामीण कृषि श्रमिकों के रोजगार की प्रकृति, निरंतरता तथा मौसमी स्वरूप का विश्लेषण करना।
- कृषि श्रमिकों की आय संरचना, मजदूरी स्तर एवं जीवन-यापन की दशाओं का मूल्यांकन करना।
- ग्रामीण कृषि श्रमिकों के समक्ष विद्यमान प्रमुख सामाजिक-आर्थिक समस्याओं—जैसे बेरोजगारी, अल्प-रोजगारी, प्रवासन एवं सामाजिक सुरक्षा की पहचान करना।
- जौनपुर जिले में कृषि के अतिरिक्त उपलब्ध गैर-कृषि रोजगार अवसरों की भूमिका एवं प्रभाव का अध्ययन करना।
- ग्रामीण कृषि श्रमिकों की स्थिति में सुधार हेतु नीतिगत एवं व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पनाएँ :

प्रस्तुत अध्ययन को दिशा प्रदान करने तथा तथ्यों के परीक्षण हेतु निम्नलिखित शोध-परिकल्पनाएँ निर्धारित की गई हैं—

1. जौनपुर जिले में ग्रामीण कृषि श्रमिकों की रोजगार संरचना मुख्यतः मौसमी एवं अस्थायी प्रकृति की है।
2. ग्रामीण कृषि श्रमिकों की आय का स्तर न्यून है, जिसका सीधा प्रभाव उनके जीवन-यापन एवं सामाजिक स्थिति पर पड़ता है।
3. कृषि कार्यों की मौसमी प्रकृति के कारण जौनपुर जिले के ग्रामीण कृषि श्रमिकों में बेरोजगारी एवं अल्प-रोजगारी की समस्या व्यापक है।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि रोजगार के सीमित अवसर कृषि श्रमिकों को प्रवासन के लिए बाध्य करते हैं।
5. सरकारी रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ ग्रामीण कृषि श्रमिकों को आंशिक राहत प्रदान करती हैं, किंतु उनकी समग्र रोजगार समस्या का पूर्ण समाधान नहीं कर पाती।
6. ग्रामीण कृषि श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर शिक्षा स्तर का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
7. महिला कृषि श्रमिकों को पुरुष श्रमिकों की तुलना में कम मजदूरी एवं अधिक कार्य-असुरक्षा का सामना करना पड़ता है।
8. सरकारी रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ (जैसे मनरेगा) ग्रामीण कृषि श्रमिकों को आंशिक राहत प्रदान करती हैं, किंतु उनकी रोजगार समस्या का स्थायी समाधान नहीं कर पाती।
9. कृषि में मशीनीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति से ग्रामीण कृषि श्रमिकों के रोजगार अवसरों में कमी आई है।
10. कौशल विकास एवं वैकल्पिक आजीविका के अवसरों के अभाव में ग्रामीण कृषि श्रमिक कृषि कार्यों पर ही अत्यधिक निर्भर बने हुए हैं।

परिकल्पना के प्रकार

व्यवहार में वैज्ञानिक अपने अनुसंधानों में कई प्रकार की परिकल्पनाओं का प्रयोग करते हैं जो निम्नलिखित हैं:

- सकारात्मक उपकल्पना
- नकारात्मक उपकल्पना
- शून्य उपकल्पना

किसी भी शोधकार्य को सुविधाजनक बनाने हेतु शून्य परिकल्पना अनुसंधान हेतु सर्वोत्तम होती है।

शून्य परिकल्पना

इसमें यह मानकर चलते हैं कि जो चर जिसमें सम्बन्ध ज्ञात करने जा रहे हैं उनमें कोई अन्तर नहीं है। NULL जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शून्य, अतः इस परिकल्पना को शून्य परिकल्पना कहते हैं।

शून्य परिकल्पना को नकारात्मक उपकल्पना इस अर्थ में मानते हैं कि प्रयुक्त चरों में कोई सम्बन्ध नहीं है। यह निर्देशन रहित होती है। अनुसंधानकर्ता को स्वीकार व अस्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता है।

शोध में परिकल्पनाओं की पुष्टिकरण के लिए कुछ शून्य परिकल्पनाओं का निर्माण किया है जिसकी सार्थकता की जाँच सहसम्बन्ध तथा क्रांतिक अनुपात द्वारा की गयी है।

अनुसंधान विधि

प्रस्तुत अध्ययन में ग्रामीण कृषि श्रमिकों की रोजगार संरचना का विश्लेषण करने हेतु वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अनुसंधान विधि अपनाई गई है। अनुसंधान की रूपरेखा, डेटा स्रोत, नमूना चयन तथा विश्लेषण विधियों का प्रयोग किया गया है।

यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है, जिसमें ग्रामीण कृषि श्रमिकों की वर्तमान रोजगार संरचना एवं उससे जुड़ी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का अध्ययन किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र

जौनपुर जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। भूमि जोत का आकार अपेक्षाकृत छोटा एवं खंडित है, जिसके कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवार स्वयं की कृषि भूमि पर निर्भर न रहकर कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। सीमित औद्योगिक विकास और गैर-कृषि रोजगार अवसरों की कमी के कारण ग्रामीण कृषि श्रमिकों की आजीविका का प्रमुख साधन खेतिहर मजदूरी ही है।

सामाजिक संरचना की दृष्टि से जौनपुर जिले में विभिन्न सामाजिक वर्गों एवं जाति समूहों का निवास है, जिनमें अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। इन वर्गों की आजीविका का मुख्य आधार कृषि श्रम है, जिससे यह क्षेत्र ग्रामीण कृषि श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक अध्ययन के लिए विशेष महत्व रखता है। अतः जौनपुर जिले को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित करना तर्कसंगत एवं उपयोगी है, क्योंकि यह क्षेत्र ग्रामीण कृषि श्रमिकों की रोजगार संरचना, समस्याओं और संभावनाओं का वास्तविक एवं व्यापक चित्र प्रस्तुत करता है।

अध्ययन की सीमाएँ

- अध्ययन जौनपुर जिले के चयनित ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित है।
- कुछ आँकड़े उत्तरदाताओं की स्मृति एवं व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित हैं।
- समय एवं संसाधनों की सीमाओं के कारण नमूना आकार सीमित रखा गया है।

आँकड़ों के स्रोत

अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का उपयोग किया गया है—

प्राथमिक आँकड़े: जौनपुर जिले के चयनित ग्रामों में ग्रामीण कृषि श्रमिकों से साक्षात्कार एवं प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र किए गए।

द्वितीयक आँकड़े: जनगणना रिपोर्ट, NSSO रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण, सरकारी प्रकाशन, शोध-पत्र, पुस्तकों एवं पत्रिकाओं से प्राप्त किए गए।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन "उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के विशेष संदर्भ में ग्रामीण कृषि श्रमिकों की रोजगार संरचना" ग्रामीण अर्थव्यवस्था के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील वर्ग की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करता है। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि जौनपुर जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है, किंतु कृषि पर निर्भर श्रमिकों की रोजगार व्यवस्था अस्थिर, मौसमी और असुरक्षित बनी हुई है। अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि ग्रामीण कृषि श्रमिकों का जीवन मुख्यतः खेतिहर मजदूरी पर आधारित है, जिसमें कार्य की

उपलब्धता मौसम, वर्षा और फसल चक्र पर निर्भर करती है। कृषि कार्य के अतिरिक्त समय में पर्याप्त वैकल्पिक रोजगार के अभाव के कारण श्रमिकों को बेरोजगारी, अल्प-रोजगार और आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति न केवल उनकी आय को प्रभावित करती है, बल्कि उनके सामाजिक जीवन और भविष्य की संभावनाओं को भी सीमित करती है।

यह भी निष्कर्ष निकला कि भूमि जोत का अभाव और कृषि भूमि का खंडित स्वरूप ग्रामीण कृषि श्रमिकों की प्रमुख समस्या है। अधिकांश श्रमिक भूमिहीन या सीमांत किसान हैं, जिनके पास आजीविका के स्थायी साधन उपलब्ध नहीं हैं। सीमित संसाधनों के कारण वे आधुनिक कृषि तकनीकों, शिक्षा और कौशल विकास से वंचित रह जाते हैं।

अध्ययन में यह तथ्य भी उभरकर सामने आया कि मनरेगा जैसी सरकारी योजनाओं ने कृषि-ऑफ सीजन में रोजगार उपलब्ध कराने में कुछ हद तक सहायता की है, परंतु यह सहायता पर्याप्त नहीं है। योजनाओं का लाभ सभी पात्र श्रमिकों तक नहीं पहुँच पा रहा है, जिसके पीछे जागरूकता की कमी, प्रशासनिक जटिलताएँ और स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन की कमजोरियाँ प्रमुख कारण हैं।

अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जौनपुर जिले के ग्रामीण कृषि श्रमिकों की रोजगार संरचना में सुधार हेतु केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि गैर-कृषि ग्रामीण रोजगार, कौशल विकास, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और प्रभावी सरकारी हस्तक्षेप की भी अत्यंत आवश्यकता है।

समग्र रूप से यह अध्ययन दर्शाता है कि यदि ग्रामीण कृषि श्रमिकों की रोजगार संरचना को सुदृढ़ और स्थायी बनाया जाए, तो न केवल श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्राप्त होगी। अतः नीति-निर्माताओं, प्रशासन और समाज को संयुक्त प्रयासों के माध्यम से इस दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

संदर्भ-सूची

1. शर्मा, आर. के.(2015) ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं कृषि श्रमिक. नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।
2. सक्सेना, एन. सी.(2013) भारत में कृषि श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति. नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन्स।
3. अग्रवाल, बी.एल.(2011) ग्रामीण विकास और रोजगार. दिल्ली: अटलांटिक पब्लिशर्स।
4. धर, पी. के. (2010) ग्रामीण भारत में श्रम संरचना. कोलकाता: प्रोग्रेसिव पब्लिशर्स।
5. शर्मा, अरुणा (2014) महिला कृषि श्रमिक समस्याएँ एवं संभावनाएँ. जयपुर, रावत पब्लिकेशन्स।
6. वर्मा, मीना(2016) ग्रामीण श्रमिकों का प्रवासन अध्ययन. लखनऊ: उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान।
7. सैनी, अमित कुमार एवं मोर्य, अजीत कुमार (2018) उत्तर प्रदेश में कृषि श्रमिकों की स्थिति. इलाहाबाद: लोकभारती प्रकाशन।
8. कुमार, बी. एन. (2012) ग्रामीण भारत में रोजगार की चुनौतियाँ. नई दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
9. भारत सरकार (2021) आर्थिक सर्वेक्षण. नई दिल्ली, वित्त मंत्रालय।
10. भारत सरकार (2020) जनगणना 2011 उत्तर प्रदेश जिला हैंडबुक-जौनपुर, नई दिल्ली: रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया।
11. योजना आयोग (2014) ग्रामीण विकास पर रिपोर्ट, नई दिल्ली, भारत सरकार।
12. नीति आयोग (2018)ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका रिपोर्ट. नई दिल्ली, भारत सरकार।
13. श्रम ब्यूरो (2019) ग्रामीण मजदूरी सांख्यिकी. चंडीगढ़, भारत सरकार।
14. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (2020). कृषि सांख्यिकी भारत, नई दिल्ली, भारत सरकार।
15. जिला सांख्यिकी पत्रिका,जौनपुर (2022), जौनपुर जिला सांख्यिकीय विवरण, जौनपुर, जिला प्रशासन।